IAS Mentorship

Reyasat Ali sir & Experienced team in CSE prep

CSE Main 2023: Mini Mock Test 2

Syllabus:	• • Indian Society • •	
Name of Candidate	MOHAN MANGAWA	
Email Id		
Date	03/07/23	Medium: Hindi / English
Time: 1 Hour	Start Time: 10PM	End Time: 11:38

Q. No.	Max. Marks	Marks obtained
1	10	
2	10	
3	10	
4	15	
5	15	
6	15	
7	15	
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
Total	90	
Invigilator	Signature	

WhatsApp/Telegram/Text/Call: 8090528260

	Excellent	Good	Average	Unsatisfied
Introduction				
Conceptual Understanding				
Contextual Clarity				
Content Enrichment				
Presentation				
Alignment				
Contextual Justification				

IAS Mentorship

By Reyasat Ali & Team I 8090528260 Telegram WhatsApp Call

Q1. Even India@75 Caste identity is deep rooted concept in India, which is one of the main causes for the Inequality at social level. Analyse causes and suggest measures for a more egalitarian and open-minded society for future India. 150 words

भारतीय समाज की विविधतापूर्ण विशेषताओं में जाति व्यवस्था सबसे प्रखर है जो अंतः धार्मिकता के बीच बँटवारे का कार्य २१वीं शताब्दी में भी कर रही है। नीति आयोग की India@75 ने भी इसे गहन विश्लेषण के बाद चिंता का विषय करार दिया।

जाति व्यवस्था के कारण

- प्राचीन वर्ण व्यवस्था → चतुः वर्णों के आधार पर आगे जाति व्यवस्था बनी।
- ब्राह्मण वर्ग का प्रभुत्व
- जातियों की अंतर्द्वन्द्वता के कारण → आपसी उप-जातियों में विभाजन
- बाहरी धर्मों - मुस्लिम, ईसाई में भी प्रभाव
- आर्थिक विभाजन → कार्य के कारण → शूद्र व वैश्य आधारित

↳ सामाजिक जड़ता व राजनीतिक इच्छा का अभाव → राजनीति का जातीयकरण

↳ वर्ग आधारित आरक्षण में जाति एक मुख्य भाग

प्रमुख कदम → वर्ग आधारित आरक्षण का तार्किकरण → उदा० EWS आरक्षण

↳ सामाजिक उद्धार व समावेशन कार्यक्रम
↳ जागरूकता, सफल लोगों के उदाहरण

↳ अनुनयन प्रक्रिया ⇒ जाति पूर्वाग्रहों को रोकने हेतु

↳ स्कूली शिक्षा में नैतिक व्यावहारिक शिक्षा को जोड़ने की जरूरत

↳ कानूनी प्रावधानों का सख्ती से पालन जरूरी
→ जरनैल सिंह वाद → क्रीमीलेयर वर्गीकरण
→ SC-ST अत्याचार अधि. 1989

इस प्रकार जाति जड़ता की समस्या बेहतर प्रशासनिक मशीनरी व समाज की बेहतर पहल द्वारा ही तीव्रता से सुलझाई जा सकती है।

Q2. Do you think that India needs a population control law at present? Critically Comment 150 words

हाल ही में UNFPA की औपचारिक रिपोर्ट द्वारा भारत 142 करोड़ आबादी के साथ विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश बन गया है। लेकिन बढ़ती संसाधन समस्याओं व सामाजिक – आर्थिक कारकों ने इस ओर कानून निर्माण के वाद - विवाद को हवा दी है।

कानून की जरूरत

हाँ

- बढ़ती जनसंख्या पर नियंत्रण जरूरी
- संसाधन सीमित → बेरोजगारी, गरीबी का कारण
- बढ़ता सांप्रदायिक उन्माद व एक धर्म विशेष को कारण मानना
- आर्थिक रूप से भी एक वहनीय साधन नहीं

नहीं

- जनसंख्या नियंत्रण हेतु अन्य उपाय → जागरूकता व परिवार नियोजन
- व्यक्तिगत स्वतंत्रता का मुद्दा। → मानवाधिकार
- NHFS – V के अनुसार रिप्लेसमेंट दर से नीचे 2.0 प्राप्ति।

→ कानूनी रूप से जनसंख्या नियंत्रण सामाजिक एकता को पहुँचा है सहिष्णुता व आपसी

→ विश्वास बहाली

→ जनसांख्यिकी लाभांश शिक्षा-स्वास्थ्य सुविधा आधारित है न कि जनसंख्या ↑

→ बेहतर अवसंरचना व आर्थिक लाभ हेतु जनसंख्या लाभांश जरूरी

Ex चीन द्वारा प्रगति

कदमों की जरूरत

↳ उच्च स्तरीय समिति गठन
  ↳ इसमें धार्मिक-जातीय प्रतिनिधियों को मौका मिले

↳ बेहतर नियम-प्रणाली बनाकर पब्लिक डोमेन में पक्ष-विपक्ष हेतु रखना।

↳ प्राकृतिक अधिकारों को देखते हुए कानून की बजाय आधारभूत ढाँचे व शिक्षा-स्वास्थ्य पर जोर ⇒ बेरोजगारी हेतु कौशल विकास

↳ समाज हित में सोशल मीडिया जागरूकता व कम बच्चे उत्पन्न पर कुछ लाभ आधारित प्रोत्साहन मदद कर सकता है।

IAS Mentorship

By Reyasat Ali & Team | 8090528260 Telegram WhatsApp Call

Q3. Analyse the role of digital technologies in women's lives, also to ensure gender equality in recent time.
150 words

* नारीवादी चिंतक ब्रेन पेब्लस के अनुसार समाज की प्रगति की कुंजी नारी-उत्थान है और बदलते परिवेश का सबसे ज्यादा असर भी उसी पर हो रहा है। इसी परिप्रेक्ष्य में तकनीकी ने महिलाओं के संबंध में कई परिवर्तन किए हैं।

तकनीकी के महिलाओं पर प्रभाव

सकारात्मक → रोजगार तक बेहतर पहुँच
↳ ऑनलाइन व घर से कार्य सुविधा
→ ग्रामीण क्षेत्रों में लड़कियों की शिक्षा में मदद → दूरस्थ शिक्षण संभव
↳ सोशल मीडिया द्वारा महिलाओं के प्रति पूर्वधारणाओं को बदला ⇒ स्वतंत्र अभिव्यक्ति की आजादी प्रदान की
↳ चिकित्सा तकनीकी में ART, टेस्ट ट्यूब बेबी, आयरन कमी हेतु पेटी आदि द्वारा महिलाओं को सहयोग

नकारात्मक → पोर्नोग्राफी व यौन शोषण को ↑
↳ महिलाओं की अस्मिता संबंधी गोपनीयता पर चोट
↳ फेक न्यूज व डिफेमेशन के तरीके ⇒ मुख्यतः महिलाओं के प्रति ⇒ इंडिया, वंटरनेट रिपोर्ट।
↳ मानसिक अवसाद व शारीरिक बीमारियों के रूप में प्रभावित

समाधान / आगे की राह
↳ बेहतर सोशल मीडिया विनियमन (सोशल मीडिया इंटरमीडियरी रूल्स 2020)
↳ महिलाओं की शिकायतों हेतु ऑनलाइन पोर्टल → हिम्मत पोर्टल, SHe बॉक्स।
↳ शिकायत निवारण हेतु तंत्र विकास व मानसिक यातना की शिकार महिलाओं हेतु मनोवैज्ञानिक सिकित्सक।

इस प्रकार महिला सक्षमता के राह में डिजिटल तकनीकी के दोनों भूमिका निभाई पड़ती एक जागरूक समाज की प्राप्ति हेतु इन समस्याओं को समझते हुए सुलझाना सकारात्मक समाज का कर्तव्य है।

Q4. Discuss the factors that affect the marriage of an Indian women/girl child in rural and urban areas both. Up to what level education has been a solution against early marriage. Justify your views. 250words

NCRB के हाल के डाटा के अनुसार पिछले तीन सालों में बाल विवाह की दर में 13% की बढ़ोतरी हुई है जो कि लड़कियों की दयनीय स्थिति की द्योतक है।

प्रभावित करने वाले कारक

ग्रामीण क्षेत्र
- अशिक्षा ⇒ अजागरूकता
- आर्थिक तंगी ⇒ बेरोजगारी
- सामाजिक प्रथा के रूप में मान्य
  - जल्दी विवाह को आर्थिक लाभ के रूप में देखना
- लड़कियों को बोझ के रूप में
  - 'कुलदीपक' अवधारणा की मान्यता

शहरी क्षेत्रों में
- बदलती जीवनशैली से सामंजस्य न कर पाना
- गरीबी ⇒ शहरी क्षेत्रों में रोजगार अवसर कम

↳ बढ़ते यौन शोषण अपराधों का डर
↳ कम्युनिटी प्रभाव ⇒ आस-पास के वातावरण ⇒ स्लम बस्तियों व गहरी आबादी क्षेत्रों में बाल विवाह अधिक

शिक्षा की इस संबंध में भूमिका

① जागरूकता में
↳ व्यक्तिगत ⇒ परिवार, लड़कियों को
↳ सामाजिक ⇒ बाल विवाह के नकारात्मक पक्षों के बारे में

② स्त्री को आत्मनिर्भर बनाने में
↳ परिवार की आर्थिक हालत को सुधारना
↳ रोजगार तक पहुँच ⇒ सशक्तिकरण का मार्ग
↳ सामाजिक स्वतंत्रता ⇒ आर्थिक मजबूत स्थिति से तीव्र होती है।

③ अधिकारों के बारे में अवगत कराकर
↳ शिक्षित लड़की बेहतर समाज व अधिकारों का उपयोग कर सकती है।

④ तकनीकी व नवाचारों तक पहुँच स्थापित करना

↳ शिक्षा महिला को तकनीकी द्वारा सर्व-कल्याण व खुद के प्रयोग हेतु सक्षम बनाती है।

↳ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स तक पहुँच

सरकार → सामाजिक अनुनयन → समाज व लोगों को सख्त संदेश देकर

↳ कानूनों का सख्ती से पालन

↳ सजा अवधि बढ़ाकर

↳ बुक ऑफ बर्डन दोनों पक्षों पर डालना।

↳ स्कॉलरशिप व स्त्री शिक्षा हेतु प्रोत्साहन → बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ

↳ शिक्षा के PPP मॉडल को अपनाकर पिछड़े लोगों तक पहुँचना ⇒ यहीं बाल विवाह ज्यादा → अतः शिक्षा

इस प्रकार एक शिक्षित नारी जरूरी। एक पूरे समाज का निर्माण करने की क्षमता रखती है, अतः पढ़ाने-बढ़ाने के साथ उनके सशक्तिकरण पर भी जोर ताकि बाल विवाह जैसी कुरीतियों के खिलाफ स्वयं आवाज उठाए।

Q5. "The ideal solution of depleting ground water resources in India is water harvesting system." How can it be made effective in urban areas? 250 words

नीति आयोग की वॉटर मैनेजमेंट इंडेक्स के अनुसार भारत का भू-जल स्तर प्रति 3-4 फीट नीचे जा रहा है जो आने वाले सालों में पेयजल, कृषि व सुखा जैसी समस्याएं उत्पन्न करेगा।

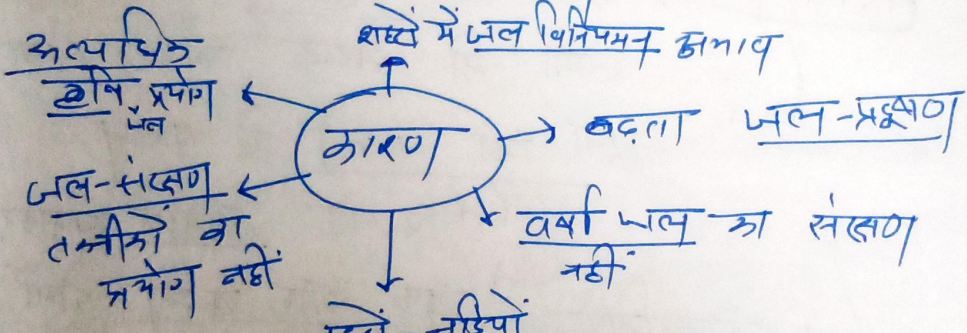

वर्षा जल संरक्षण के लाभ

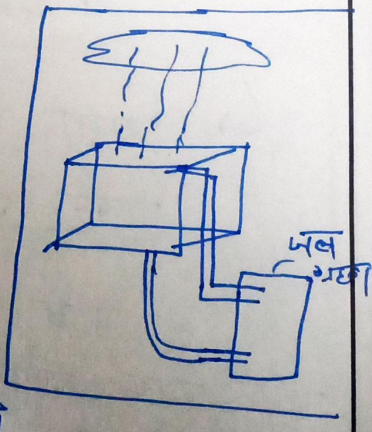

1. सूखे क्षेत्रों हेतु जीवन-दायक
2. कृषि में ड्रिप सिंचाई हेतु उपयोग संभव
3. शुद्धतम जल प्राप्त की प्राप्ति
4. भूमि नमी को बनाये रखने में सहायक

⑤ शहरी बाढ़ को रोकने का हल ⇒ कम जल बहाव से

⑥ जल का आर्थिक मूल्य रूप में बदलना
↳ जल प्राप्ति हेतु ज्यादा धन खर्च की जरूरत नहीं।

⑦ आस-पास के जैव-पर्यावरण को बचाये रखने में सहायक ⇒ नमी द्वारा

शहरी क्षेत्रों में प्रभावी बनाने हेतु उपाय

① वर्षा जल संरक्षण हेतु जागरूकता ⇒ सोशल मीडिया, NGOs व स्कूली वर्कशॉप्स द्वारा

② जल टैंक बनाने हेतु सब्सिडी आधारित मॉडल

③ वॉटर ट्रेडिंग ⇒ नेट मीटरिंग का प्रयोग करके ⇒ एक निश्चित दर पर
⇒ मलेशिया मॉडल

④ एक सोशल चेंज ⇒ पानी के बचाव हेतु भावनात्मक परिवर्तन जरूरी

↳ स्थानीय स्वशासन निकायों के प्रतिनिधियों द्वारा प्रोत्साहन कार्यक्रम

समस्याएँ:

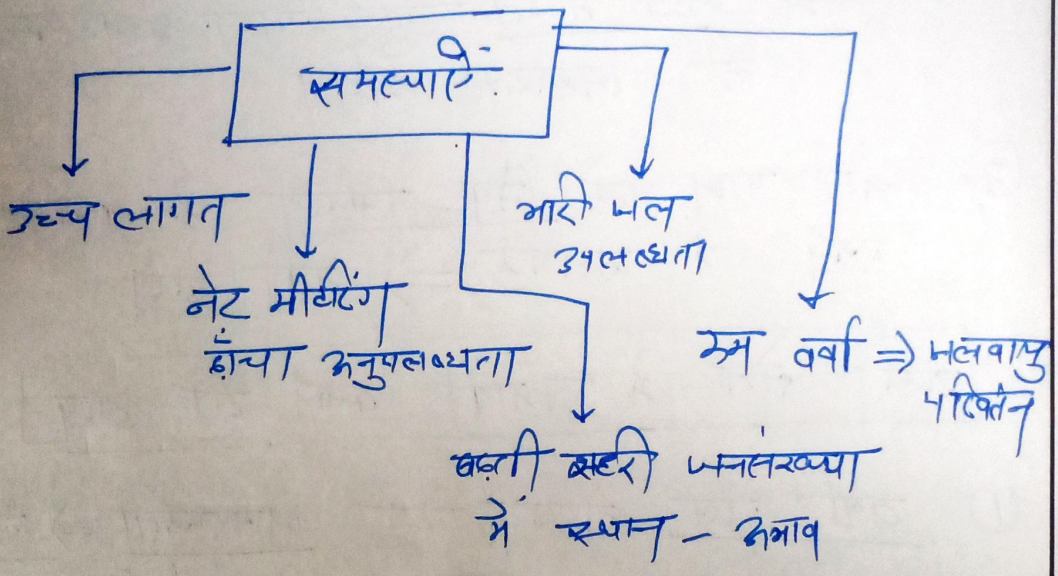

- उच्च लागत
- नेट मीटरिंग ढांचा अनुपलब्धता
- बढ़ती शहरी जनसंख्या में स्थान - अभाव
- भारी जल उपलब्धता
- कम वर्षा ⇒ जलवायु परिवर्तन

समाधान → हाइब्रिड मॉडल → सोसायटी आधारित वर्षा जल संरक्षण [illegible]

→ प्रोत्साहन राशि व लाभार्थियों का प्रचार प्रसार अनुनयन बढ़ायेगा।

→ जलवायु परिवर्तन रोकने हेतु वृक्षारोपण व प्रदूषण कम करने पर जोर।

अतः 'जल ही जीवन है' तभी बचेगा जब जनता इस जीवनदान को पर्याप्त रूप से संचित करेगी।

Q6. Despite several efforts for poverty alleviation, there is no doubt that ending poverty remains a challenging task. Comment 250 words

नीति आयोग ने अपनी प्रथम 'बहुआयामी गरीबी सूचकांक' में भारत की गरीबी ~27% बताई है जो कि देश के एक बड़े हिस्से को किसी ना किसी प्रकार की गरीबी की समस्या से ग्रसित बताती है।

सतत् गरीबी के कारण

सामाजिक
- → गरीबी का एक प्रथा के रूप में
- → दलित - LGBTQA+ आदि समूहों का सामाजिक बहिष्करण
- → अवसरों की असमानता ⇒ संसाधनहीनता

आर्थिक
- → बढ़ता पूंजीवाद ⇒ ऑक्सफैम के अनुसार
  - ↳ कोविड अमीर - गरीब की खाई बढ़ी।
- → संसाधनों व रोजगार तक सीमित पहुंच
- → शिक्षा का प्रसार कुछ ही क्षेत्रों तक
  - ↳ महिलाओं में निरक्षरता अधिक
    - ↳ गरीबी तीव्रता अधिक

गवर्नेंस → सरकारी नीतियों का कार्यान्वयन नहीं
→ प्रशासनिक भ्रष्टाचार ⇒ PDS, स्वास्थ्य योजनाओं, मनरेगा आदि में
→ शिकायत निवारण प्रणाली अभाव

अन्य → स्वास्थ्य कुपोषण ⇒ जनसांख्यिकीय लाभांश नहीं ⇒ गरीबी की प्रवृत्ति तीव्र
→ शहरी बढ़ती जनसंख्या
→ व्यवसायों का तकनीकीकरण
→ कौशलाभाव व शिक्षा प्रणाली में व्यापक कमियाँ ⇒ रोजगार उत्पन्नमूलक नहीं

गरीबी कम करने हेतु प्रयास-उपाय

→ प्रशासनिक गवर्नेंस द्वारा इफेक्टिव-सेवा-प्रदाता मॉडल
→ मनरेगा व DAY-NULM-NRLM जैसे रोजगार प्रदान कार्यों का संचालन ⇒ जियो टैगिंग
→ पंचायती स्तरों पर → PRIs को माइक्रो-प्लानिंग हेतु वित्त की जरूरत ⇒ PDS व JAM-DBT कार्यों की प्रभाविता हेतु जरूरी।

↳ शहरी क्षेत्रों में स्लम-पुनरउद्धार कार्यक्रम व शहरी मनरेगा → RJ मॉडल अपनाना।

↳ कौशल युक्त शिक्षा व माइक्रो-फाइनेंसिंग द्वारा SHGs, MSMEs आदि को बढ़ावा
↳ रोजगारमूलक

↳ स्वास्थ्य व कुपोषण पर ध्यान ⇒ निरंतर मुफ्त इलाज (BPL हेतु) व पोषण उपलब्धता। (PDS पर मोटा अनाज)

↳ सामाजिक न्यायीकरण ⇒ SC/ST हेतु आरक्षण में सब-कैटेगराइजेशन (जरनैल सिंह वाद) व LGBTQAI+ हेतु नौकरियों में आरक्षण।

इस प्रकार सामाजिक-आर्थिक उत्पादन हेतु पहले शिक्षा-स्वास्थ्य पर ध्यान देते हुए कौशल की ओर विकास द्वारा ही इस बढ़ती बेरोजगारी द्वारा उत्पन्न गरीबी को कम किया जा सकता है।

Q7. Discuss the various causes of regionalism and their impacts in short and long run. 250 words

समाजशास्त्री टी.के. ओमेन के अनुसार किसी क्षेत्र में अपने विभिन्न प्रकारों जैसे भाषा, जाति, नृजातीयता आदि के प्रति जब आवश्यकता से अधिक संरक्षण का भाव उत्पन्न होने लगता है तो यह क्षेत्रवाद की शुरुआत है।

क्षेत्रवाद किसी भी देश को सकारात्मक व नकारात्मक दोनों रूपों में प्रभावित कर सकता है। इसके **कारण** भी बड़े विस्तृत होते हैं-

- भाषा-क्षेत्र आधारित → तमिल व बोडो क्षेत्र
- अलगाववाद को बढ़ाने हेतु → पंजाब खालिस्तानी
- राज्य निर्माण को लेकर → सौराष्ट्र, विदर्भ
- बाहरी राज्यकर्ता द्वारा संचालन → कश्मीरी अलगाववाद
- विकास संबंधी असमानता से उत्पन्न → नक्सली

प्रभाव

सकारात्मक

- अपनी संस्कृति के प्रति जागरूकता
- विविधता में एकता ⇒ संवैधानिक मूल्य
- क्षेत्रीय विकास हेतु आवाज जरूरी
- क्षेत्रीय भावनाओं को राष्ट्रीय स्तर पर आवाज - समर्थन प्राप्ति।

नकारात्मक पक्ष

Short Run

- भारी हिंसा - झड़पें → असम-मिजो., मणिपुर हिंसा
- AFSPA, इन्टरनेट शटडाउन जैसे प्रभाव
- जान-माल का नुकसान
- दैनिक गतिविधियों पर अंकुश
- अन्य क्षेत्रों के लोगों के साथ हिंसा ⇒ MH में बिहार-UP आदि के प्रति

Long Run

सामाजिक

- सामाजिक द्वेष भावना प्रसार
- संघर्ष व अंतः क्षेत्रीय कट्टरता
- सांप्रदायिक व संवेदनशील वर्गों पर हिंसा ⇒ सामाजिक विकास अवरुद्ध

आर्थिक → ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को नुकसान
→ संसाधनों का प्रयोग नहीं ⇒ बेरोजगारी गरीबी

प्रशासनिक → सरकारी मशीनरी का समय दंगे रोकने में खर्च
→ योजनाओं का क्रियान्वन नहीं होना।
→ शिक्षा-स्वास्थ्य जैसे आयाम पीछे छूट जाना ⇒ अकुशल व कुपोषित क्षेत्रीय जनसंख्या।

समाधान → अन्तर्राज्यीय परिषदों, क्षेत्रीय परिषदों द्वारा सद्भाव पर जोर
→ उभरते मुद्दों का तीव्रता से निवारण
→ बाहरी राज्य कर्ताओं व संगठित अपराधों के समन्वय का पर्दाफाश हेतु खुफिया एजेंसी
→ क्षेत्रीय असमानता को कम करने हेतु सहकारी संघवाद व अवसंरचना विकास पर जोर
→ त्रिभाषा-फार्मूला, पूर्वोत्तर की कनेक्टिविटी, नक्सलवादी क्षेत्रों में संसाधन-कर्षण को कम करने हेतु समावेशी विकास पर जोर देना जरूरी।